भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या4256
जिसका उत्तर 26 मार्च, 2025 को दिया जाना है ।
05चैत्र, 1947 (शक)

आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का विस्तार

4256 श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को स्वीकृत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण परियोजनाओं का ब्यौरा बापतला में नियोजित परियोजनाओं सहित क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन (फैब) इकाइयों, चिप डिजाइन केंद्रों या इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टरों (ईएमसी) की स्थापना के लिए कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई;

(ग) इन पहलों के माध्यम से राज्यवार विशेषकर आंध्र प्रदेश में कितने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं;और

(घ) मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत सेमीकंडक्टर उत्पादन में निजी निवेश आकर्षित करने और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (घ) :सरकारनेदेशमेंसेमीकंडक्टरऔरडिस्प्लेविनिर्माणपारिस्थितिकीतंत्रकेविकासकेलिए 76,000 करोड़रुपएकेकुलपरिव्ययकेसाथसेमीकॉनइंडियाकार्यक्रमकोमंजूरीदीहै, जोनिम्नलिखितप्रदानकरताहै:

i. भारतमेंसिलिकॉनपूरकमेटल-ऑक्साइड-सेमीकंडक्टर (सीएमओएस) आधारितसेमीकंडक्टरफैब्सकीस्थापनाकेलिएपरियोजनालागतका 50% समानआधारपरराजकोषीयसमर्थन ।
ii. भारतमेंडिस्प्लेफैबकीस्थापनाकेलिएसमरूपआधारपरपरियोजनालागतका 50% राजकोषीयसमर्थन।
iii. भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (माइक्रो-इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम सहित) फैब / डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (ओएसएटी) सुविधाओं की स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय के 50% की राजकोषीय सहायता।
iv. प्रोडक्ट लिंक्ड इन्सेंटिव पात्रव्ययके 50% तकहोगाजिसकीअधिकतमसीमाप्रतिआवेदन 15 करोड़रुपएहोगी। इसकेअलावा, चिपडिजाइनकोप्रोत्साहितकरनेकेलिएप्रतिआवेदन 30 करोड़रुपएकीअधिकतमसीमाकेअधीन 5 वर्षोंमेंशुद्धबिक्रीकारोबारके 6% से 4% तकका "डिप्लोयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव" भीदिया जाएगा।

सरकारनेमोहालीस्थितसेमीकंडक्टरप्रयोगशालाकेआधुनिकीकरणकोभीमंजूरीदेदीहै। इसकेअलावा, सेमीकंडक्टरपारिस्थितिकीतंत्रकेविकासमेंसहयोगकेलिएसिंगापुर, अमेरिका, यूरोपीयसंघऔरजापानकेसाथसमझौताज्ञापनपरहस्ताक्षरकिएगएहैं।

सेमीकॉनइंडियाकार्यक्रमकेतहतसरकारनेलगभग 1,52,000 करोड़रुपएकेसंचयीनिवेशकेसाथपाँच (5) सेमीकंडक्टरविनिर्माणपरियोजनाओंकोमंजूरीदीहै। इसकेअलावा, भारतीयउत्पादोंकेलिएचिप्सडिजाइनकरनेकेलिएडिज़ाइनलिंक्डइंसेंटिवस्कीमकेतहत 17 सेमीकंडक्टरडिज़ाइनकंपनियोंकोमंजूरीदीगईहै। इसकेअतिरिक्त, इसयोजनाकेतहतउपलब्धकराएगएईडीएउपकरणोंतकपहुँचकेलिए 64 सेमीकंडक्टरडिज़ाइनकंपनियोंकोमंजूरीदीगईहै।

इसकेअलावा, चिप्सटूस्टार्ट-अप (सी2एस) कार्यक्रमसेमीकंडक्टरचिपडिजाइन, वीएलएसआई (बहुतबड़ेपैमानेपरएकीकरण) औरएम्बेडेडसिस्टमडिजाइनक्षेत्रोंमेंविशेषज्ञतावाले 85,000 उद्योग-तैयारजनशक्तितैयारकरनेकेलिएशुरूकियागयाएकव्यापककार्यक्रमहै। सी2एसकार्यक्रमकेतहत, आंध्रप्रदेश (आ°प्र°) राज्यमें 4 आरएंडडी परियोजनाओंकोमंजूरीदीगईहै। इसकेअलावा, इसकार्यक्रमकेतहतआ°प्र°राज्यके 12 संस्थानोंकोईडीएउपकरणोंतकपहुँचप्रदानकीगईहै।

सेमीकॉनइंडियाकार्यक्रमसेअतिरिक्तसरकारनेकईयोजनाएंशुरूकीहैं, जैसेबड़ेपैमानेपरइलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणकेलिएप्रोडक्ट लिंक्ड इन्सेंटिव (पीएलआई) योजना, आईटीहार्डवेयरकेलिएपीएलआई, इलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणक्लस्टरयोजना, इलेक्ट्रॉनिकघटकोंऔरसेमीकंडक्टरोंकेविनिर्माणकोबढ़ावादेनेकीयोजना (एसपीईसीएस) औरसंशोधितविशेषप्रोत्साहनपैकेजयोजना (एम-एसआईपीएस), ताकिदेशमेंक्षमताओंकोप्रोत्साहितऔरबढ़ावादेकरभारतकोइलेक्ट्रॉनिक्ससिस्टमडिजाइनऔरविनिर्माण (ईएसडीएम) केलिएवैश्विककेंद्रकेरूपमेंस्थापितकियाजासके।

इनपहलोंकेअंतर्गत, आईटीहार्डवेयरकेलिएपीएलआईकेअंतर्गत 27 कंपनियां (आंध्रप्रदेशमें 1 सहित), पीएलआईबड़ेपैमानेपरइलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणकेअंतर्गत 32 कंपनियां (आंध्रप्रदेशमें 2 सहित), इलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणक्लस्टरयोजनाकेअंतर्गत 28 क्लस्टरऔर 4 सामान्यसुविधाकेंद्र (सीएफसी) (आंध्रप्रदेशमें 4 सहित), एमएसआईपीएसकेअंतर्गत 313 कंपनियां (आंध्रप्रदेशमें 9 सहित) कोमंजूरीदीगईहै।

(ख) : सरकारने 76,000 करोड़रुपएकेकुलपरिव्ययकेसाथसेमीकॉनइंडियाकार्यक्रमकोमंजूरीदीहैजिसमेंडिजाइनलिंक्डइंसेंटिव (डीएलआई) योजनाकेलिए 1,000 करोड़रुपएकापरिव्ययशामिलहै; जिसमेंसे 60,000 करोड़रुपएसेअधिककीराशि 5 सेमीकंडक्टरविनिर्माणपरियोजनाओंकेलिएपहलेहीप्रतिबद्धकीजाचुकीहैऔरडीएलआईकेतहतस्वीकृत 17 सेमीकंडक्टरडिजाइनकंपनियोंकेलिए 200 करोड़रुपएसेअधिककीराशिप्रतिबद्धकीगईहै। इलेक्ट्रॉनिकीऔरसूचना प्रौद्योगिकीमंत्रालयकीइलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणक्लस्टरयोजनाओंकाकुलपरिव्यय 5,232 करोड़रुपएहैजिसमेंसेलगभग 3,400 करोड़रुपएविभिन्नराज्योंमेंईएमसीकेलिएप्रतिबद्धहैं।

(ग) : इलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणकोबढ़ावादेनेकेलिएविभिन्नयोजनाओंकेतहतस्वीकृतउपरोक्तकंपनियोंनेपहलेही 6 लाखसेअधिकरोजगारकेअवसरपैदाकिएहैं। इसकेअलावा, स्वीकृत 5 सेमीकंडक्टरविनिर्माणपरियोजनाओंसेफैक्ट्रीऑटोमेशनकीपरिपक्वताकेआधारपर 26,000 सेअधिकप्रत्यक्षरोजगारकेअवसरपैदाहोनेकीउम्मीदहै।
इनइकाइयोंसेअन्यक्षेत्रोंऔरआपूर्तिश्रृंखलामेंरोजगारसृजनपरव्यापकप्रभावपड़नेकीउम्मीदहै।

*****